ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल

ऑफ़

बैंक, इन्सुरेंस एंड फाइनेंस यूनियन्स

**प्रेस विज्ञप्ति**

28 **फरवरी**, 2022

## भारत में बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ एकजुटता

भारत सरकार की स्वीकृत नीतियों के अनुसरण में, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और बैंकों और बीमा कंपनियों सहित सार्वजानिक उपक्रमों को निजीकरण के लिए लक्षित किया गया है तथा इनको निजी निहित स्वार्थो वाले कॉरपोरेट्स को सौंप दिया जा रहा है। इस नीति के एक भाग के तहत , भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को सरकार की इक्विटी शेयरधारिता के एक हिस्से को बेचकर विनिवेश और निजीकरण के लिए घोषित किया गया है।

सरकार की शेयर पूंजी के एक भाग की यह बिक्री और कुछ नहीं बल्कि LIC के अंततः निजीकरण की शुरुआत है। LIC भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में से एक है जो देश के लोगों के विश्वास का पात्र रहा है और 40 करोड़ से अधिक पॉलिसी-धारकों की सेवा कर रहा है। इसका 38 ट्रिलियन भारतीय रुपये (38 लाख करोड़ रुपये) का संपत्ति आधार है और यह सरकार के सभी बुनियादी ढांचे के विकास कार्यक्रमों में एक प्रमुख निवेशक है और इस प्रकार देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक है कि सरकार के वार्षिक राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए इस प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के निगम का अपनी पूंजी के विनिवेश के माध्यम से निजीकरण किया जा रहा है।

**TUIBIFU c / o** अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ,

सिंगापुर प्लाजा, **164** लिंगी चेट्टी स्ट्रीट, चेन्नई-**600001**, भारत

ईमेल: **chv.aibea@gmail.com** हैंडफ़ोन: **98400 89920**

यह उचित है, LIC  के कर्मचारी और अधिकारी इस अनुचित और प्रतिगामी कदम का विरोध कर रहे हैं और ट्रेड यूनियनों ने भी भारत सरकार के इस अनुचित कदम के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त करने के लिए हड़ताल की कार्रवाई करने का फैसला किया है।

LIC की ट्रेड यूनियनों के साथ उनके न्यायसंगत संघर्ष में अपनी एकजुटता व्यक्त करते हुए, हम भारत सरकार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह करते हैं।

सी.एच.वेंकटचलम

महासचिव

**TUIBIFU c / o** अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ,

सिंगापुर प्लाजा, **164** लिंगी चेट्टी स्ट्रीट, चेन्नई-**600001,** भारत

ईमेल: **chv.aibea@gmail.com** हैंडफ़ोन: **98400 89920**